

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 269 बेमेतरा, मंगलवार 26 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

2 जगहों पर श्राद्ध कर्म के दौरान आयोजित भोज खाने से 4 लोगों की मौत

झारसुगुड़ा। ओडिशा के झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ से बेहद दुःखद और चिंताजनक खबर सामने आई है। यहां 10वीं के श्राद्ध कर्म के दौरान आयोजित भोज खाने के बाद चार लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग बीमार पड़ गए। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग को इस हादसे की वजह माना जा रहा है। दोनों जिलों में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें जांच में जुट गई हैं। सबसे पहला मामला सुंदरगढ़ जिले के हेमगिरी ब्लॉक के नुआडीही गांव से सामने आया। यहां एक परिवार में 10वीं का श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गांव के कई लोग इस भोज में शामिल हुए थे और भोजन किया था। भोज खाने के कुछ समय बाद कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं होने लगीं। देखते ही देखते हालात गंभीर हो गए बीमार लोगों को तुरंत हेमगिरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 10 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

पंजाब की कपूरथला जेल में हिंसा, बैरकों में तोड़फोड़ और आगजनी का प्रयास

चंडीगढ़। पंजाब की कपूरथला जेल में रात करीब 9 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब कैदियों के 2 समूह अचानक से उग्र हो गए। देखते ही देखते आक्रोशित कैदियों ने जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने बैरकों में तोड़फोड़ करने के बाद जेल के एक हिस्से में आग लगाने का प्रयास किया। इस दौरान जेल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने हालात को काबू करने की प्रयास किया, तो कैदियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रात 9 बजे के करीब हुई। हिंसा पर उतारू कैदियों ने बैरक संख्या 4 की दीवारों को तोड़ दिया। इसके बाद आग लगाने की कोशिश की। कपूरथला जेल में हिंसा पर अभी कोई आधिकारिक बयान जेल प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आया है। घटनास्थल से कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें कैदी जेल से इसकी नींव पड़ी थी। 1983 में इसे जिला जेल के रूप में अपग्रेड किया गया। 2015 में यह आधिकारिक तौर पर एक केंद्रीय कारागार बन गया। यह आधुनिक परिसर 78 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी क्षमता 2,728 कैदियों की है। कभी-कभी यहां कैदियों की संख्या 3,900 तक हो जाती है।

पेट्रोल-डीजल के रेट चौथी बार बढ़े

पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 हुआ और महंगा....

नईदिल्ली/ एजेंसी

पेट्रोल-डीजल फिर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। इस तरह 10 दिन में पेट्रोल और डीजल लगभग 8 रुपये महंगा हो गया है। नई दरें आज यानी 25 मई की सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रो कंपनियों ने दाम बढ़ाने के पीछे ईरान युद्ध के कारण होने वाली हानि को कारण बताया है। मान्य पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि प्रीमियम ईंधनों के दाम भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं। एक्सपी 95 जो 106.63 रुपये प्रति लीटर था, वह 25 मई को 109.24 रुपये हो गया. झल को कीमत

97.81 रुपये से बढ़कर 100.52 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई। बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पहले जो डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर था, वह अब आज से 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिकेगा। यानी कि डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसी तरह से पहले पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये प्रति लीटर थी, जो आज 25 मई को बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जो कल के रेट 108.45 के मुकाबले कुछ ज्यादा है। यहां पेट्रोल की अब तक सबसे कम कीमत 6 मई को 103 रुपये प्रति लीटर थी। बता दें कि मध्य पूर्व में संकट शुरू होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई को पहली बार इजाफा किया गया था। तब दोनों ईंधनों की



कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। इसके बाद 19 मई को करीब 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। 10 मई को 23 मई) को तेल के शुरू होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई को पहली बार इजाफा किया गया था। तब दोनों ईंधनों की

वृद्धि कर दी गई है। इस तरह से 4 बार की बढ़ोतरी के बाद दाम में अब तक 7.50 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। 10 दिन में 7.50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद यात्रियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और सभी सेक्टरों के व्यवसायों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की

उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल की दरों में लगातार बढ़ोतरी से परिवहन और लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ सकता है, जिससे आखिरकार जरूरी चीजों और खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे पहले 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे लीटर जबकि डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। 23 मई को ही वाहन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले सीएनजी की कीमत में भी एक रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है।

पेट्रोल-डीजल ड्यूटी कटौती से सरकार को 1-लाख करोड़ का नुकसान : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वैश्विक संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से जनता को राहत दिलाने सरकार ने ईंधन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इस कटौती से देश भर के उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के पंपों पर कम कीमतें चुकानी पड़ रही है। यह कदम ऐसे समय में परिवारों और व्यवसायों को सीधी राहत देता है, जब पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार गहरे दबाव में बना हुआ है। सरकार के इस कदम को लेकर देश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) कम करने से सरकार को 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर बनाए जा रहे निराशाजनक माहौल को खारिज किया और देश की आर्थिक स्थिति का बचाव किया।



स्वास्थ्य मंत्री ने देश में तैयारियों का जायजा लिया

जेपी नड्डा ने लोगों को इबोल से सतर्क रहने की दी सलाह..

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इबोला वायरस रोग (ईवोडी) की तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों की समीक्षा की। यह समीक्षा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हाल ही में सामने आए प्रकोपों के मद्देनजर की गई है। भारत में इबोला का कोई भी मामला अब तक दर्ज नहीं किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भी इसे महाद्वीपीय सुरक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बताया है। नड्डा ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान देश में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया।



उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक प्रतिक्रिया उपायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता बढ़ाने और निगरानी को तेज करने के लिए भी चर्चा हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश

इबोला के लिए पूरी तरह तैयार रहे। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव उपस्थित थे। आईसीएमआर के महानिदेशक और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भी मौजूद रहे। अतिरिक्त सचिव और एनसीडीसी के निदेशक ने भी इसमें भाग लिया। मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी हुए इस हाई अलर्ट के बाद भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। केंद्र सरकार ने एहतियात के तौर पर एक विस्तृत ड्रेवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों को इबोला से प्रभावित देशों की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सख्त सलाह दी गई है। इसके साथ ही देश के सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है।

सीएम शुभेंद्रु अधिकारी ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, मुफ्त बस सेवा शुरू

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की शुभेंद्रु सरकार ने राज्य की आधी आबादी को एक बहुत बड़ा तोहफा देते हुए सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की ऐतिहासिक घोषणा की है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही यह योजना 1 जून 2026 से पूरे सूबे में लागू हो जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत राज्य की किसी भी उम्र की महिला को छोटी या लंबी दूरी की सरकारी बसों में सफर करने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। सरकार को पूरा भरोसा है कि इस कदम से कामकाजी और आम महिलाओं की हर महीने अच्छी-खासी आर्थिक बचत होगी और उनका सफर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुगम हो जाएगा।

पेट्रोल-डीजल के दाम पर राहुल ने सरकार को घेरा

चुपके-चुपके काट रहे हैं जनता की जेब-लगाए गंभीर आरोप...

नई दिल्ली/ एजेंसी

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो धीरे-धीरे तेल के दाम बढ़ाकर जनता का जेब काट रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल-डीजल के दाम किरतों में बढ़ते हैं ताकि चुपके-चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से दिनों के भीतर चौथी बार हुई आर्थिक तूफान आने की बात कह



रहा था। पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। ये बहुत होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है। चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 10 रुपये के भीतर चौथी बार हुई बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर

निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'फ्यूल लूट' का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। खड़गे ने दावा किया कि पेट्रोल की कीमत में 7.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 7.53 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खड़गे ने अपने पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने आम लोगों को बचत को जलाने का काम किया है। उन्होंने यूपीए सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए दावा किया कि 2004 से 2014 के बीच अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 175 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी, जबकि मोदी सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 में पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपए प्रति लीटर थी।

धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब जी के सानिध्य एवं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी के नेतृत्व में सतनाम सद्भाव पदयात्रा के पदयसेवाभावी एवं पत्रकार साथियों का सम्मान

बोल रहा अब हिंदुस्तान, मनखे-मनखे एक समान के संदेश से गूंजा सम्मान समारोह



मनखे-मनखे एक समान के संदेश के साथ सामाजिक समरसता का भव्य आयोजन रायपुर में संपन्न

मूक पत्रिका/रायपुर/छत्तीसगढ़— परम् पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के पावन संदेश बोल रहा अब हिंदुस्तान, मनखे-मनखे एक समान को जन-जन तक पहुंचाने हेतु आयोजित विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा, सामाजिक समरसता अभियान एवं सम्मान समारोह का आयोजन मेकाहारा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम, रायपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 18 फरवरी से 22 फरवरी तक रायपुर से गिरीदपुरी धाम तक आयोजित विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा में शामिल पदयात्रियों, आयोजन को सफल बनाने वाले सेवाभावी स्टाफ सहयोगी साथियों, कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने

वाले पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर राजागुरु, धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज को संगठित कर एकता, भाईचारा एवं सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ाना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश मानवता, समानता और सत्य का संदेश है, जिसे हम सभी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की शक्ति उसकी एकजुटता में निहित होती है और जब समाज संगठित होकर आगे बढ़ता है तो हर क्षेत्र में नई ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन आता है।

वही सतधारी गुरु गुरु सोमेश बाबा जी ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह सतनाम सद्भाव पदयात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और मानवता का महाअभियान है। उन्होंने कहा कि बाबा जी द्वारा बताए गए सत्य, अहिंसा,



सद्भावना एवं समानता के मार्ग पर चलकर ही समतामूलक एवं सशक्त समाज का निर्माण संभव है। समाज के युवाओं को बाबा जी के विचारों को आत्मसात कर समाज सेवा एवं सामाजिक जागरूकता के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन गुरु खुशवंत साहेब जी ने कहा कि



समाज को एकता, समानता एवं मानवता की भावना से जोड़ता है। और सरकार समाज के विकास को सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में आयोजन को सफलता में योगदान देने वाले समस्त स्टाफ सहयोगी साथियों एवं कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा गया कि आप सभी ने दिन-रात अथक मेहनत, सेवा भाव एवं पूर्ण समर्पण के साथ प्रत्येक व्यवस्था का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन किया। 24 घंटे निरंतर सेवा में समर्पित रहकर जिस निष्ठा, अनुशासन एवं भावनात्मक जुड़ाव के साथ आपने इस पावन आयोजन को सफल बनाया, वह अत्यंत प्रेरणादायी एवं अविस्मरणीय है। आप सभी का त्याग, परिश्रम एवं समर्पण ही इस आयोजन की सबसे बड़ी शक्ति रहा।

कार्यक्रम में राजागुरु, धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब जी, गुरु सोमेश बाबा जी, गुरु परिवार के सदस्य, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब जी, राजिम विधायक रोहित साहू जी, आयोग अध्यक्ष अंजय शुक्ला जी, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम नारंग जी, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, जांजगीर जिला पंचायत अध्यक्ष पति इंजी. आनंद मीरी जी, जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक, भाजपा एवं अखिल भारतीय सतनाम सेना के पदाधिकारी, सदस्यगण, पत्रकार बंधु, बड़ी संख्या में समाजजन एवं गुणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम में अखिल भारतीय सतनाम सेना एवं समस्त सतनामी समाज की महत्वपूर्ण सहभागिता रही।

प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर होगी कड़ी कार्रवाई-कलेक्टर

कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक,

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति समीक्षा की, उन्होंने कहा पीएम आवास योजना के तहत प्राप्त शिकायतों को गंभीरता लें तथा योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर हितग्राहियों से स्वयं चर्चा कर जांच करें तथा समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि



प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण करें तथा प्राप्त शत-प्रतिशत आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुशासन तिहार के शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, आवेदकों की समस्याओं को सुनें एवं पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान करें। कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान बैंकर्स

द्वारा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में हो रही धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने धीमी प्रगति वाले बैंकर्स को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बैठक में ठेस अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा करते हुए स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में ठेस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, ताकि ग्रामीणों को कचरा पृथक्करण, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी दे। उन्होंने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए तथा आमजन को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जाए। कलेक्टर ने आगामी पूरक परीक्षा की तैयारियों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक तैयारी कराये। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को विषयवार विशेष मार्गदर्शन दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के शहरी एवं

ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था सुचारु बनाए रखना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं भी पेयजल समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने बिजली संबंधी शिकायतों की समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति बाधित होने, ट्रांसफार्मर खराब होने अथवा अन्य विद्युत समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके। बैठक में कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ईऑफ़िस, आयुष्मान कार्ड, वय वंदना कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं आगामी खरीफ फसल की तैयारी की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

टिमरलगा में सड़क फिर हुआ लहू लुहान बाइक सवार युवक युवती की मौके पर

यातायात नियमों का खुला

उल्लंघन, ह॥ रोड पर हेवी

गाड़ियों का लंबा लाइन

सारांगढ़ /मूक पत्रिका

सारांगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत टिमरलगा में आज बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आया है बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक युवती का मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ही घटना स्थल पर ही दम तोड़ दी। मिली जानकारी के अनुसार युवक और युवती बाइक से कहीं जा रहे थे तभी यह घटना ग्राम टिमरलगा के पास घट गई है। घटना इतना भयानक था कि हादसा में दोनों के जान चली गई। हादसा को देख लोगों में बवाल सा मच गया क्या हुआ? ये आवाज कैसे है। गिरे हुए व्यक्तियों को उठाने लोगों दौड़ पड़े लेकिन हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों के जान वही



निकल गया थी। जैसे जैसे सारांगढ़ पुलिस टीम को सूचना दिया गया तथा सारांगढ़ हॉस्पिटल भेज दिया गया तथा शवों को उठकर पंचनामा के लिए सारांगढ़ हॉस्पिटल भेज दिया गया तथा जांच में सारांगढ़ पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार युवक को टेंडा नावापारा के सूरज राठिया बताया जा रहा है और लड़की को सारांगढ़ बिलाईगढ़ जिला के बिलाईगढ़ गोपालपुर धौराभाव क्षेत्र के आस पास का बता जा रहा है। दोनों का उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष तक जानकारी मिली है। फ़ित्हाल अब सारांगढ़ कोतवाली थाना जांच में छुड़ी है इससे जुड़ी और कुछ मामला सामने आ सकता है। ग्राम पंचायत

गुड़ेली टिमरलगा उद्योग क्षेत्र के वजह से रात दिन नेशनल हाईवे के बड़ी बड़ी गाड़ियों का कतार लगा होता है जो यातायात नियमों का खुला उल्लंघन करके राहगीर आम जनता को भारी आवागमन में परेशानी होता है तथा कई बड़े हादसा हो चुके हैं कई लोगों के जान चुके हैं तथा इस मुद्दे को सारांगढ़ यातायात विभाग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और नेशनल हाईवे में हेवी जो गाड़ी खड़ी है उन पर कार्यवाही की जाए ताकि आने वाला समय में ऐसी घटना ना घटे और आम जनता के प्राणों का रक्षा हो सके। तथा आम जनता यातायात नियमों का पालन करें और अपना और दूसरों का जान सुरक्षित रखें।

जिला प्रशासन के आदेशों का खुला उल्लंघन, जिला प्रशासन ने इस संवेदनशील

मामले में केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शायद अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली

पचधारी एनीकट फिर से नहाने पहुंच रहे हैं लोग

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ शहर के केलो नदी पर बने पचधारी एनीकेट में नहाने के दौरान पिछले दिनों दो लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने बड़ी संख्या में युवक और बच्चे एनीकेट पहुंच रहे हैं और छ्पाछप नहाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा भी यहां बेअसर नजर आ रही है। रायगढ़ के पचधारी एनीकेट में एक बार फिर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। तेज गर्मी और उमस से राहत पाने लोग नदी में उतरकर नहाने का आनंद ले रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले इसी एनीकेट में नहाने के दौरान दो लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं दिख रहे। खासकर युवा और बच्चे जान जोखिम में डालकर गहरे पानी तक पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने रविवार को यहां का निरीक्षण करने के दौरान पाया कि कई लोग एनीकट के बांध के उपर वाले गहरे पानी के क्षेत्र में भी नहा रहे हैं। जो कि खतरे से खाली नही है और यहीं पर पहले दो मौतें इसी साल हो चुकी है। विंडबना यह

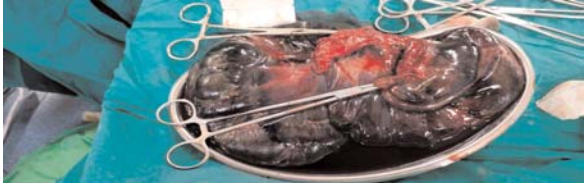


रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले इसी एनीकेट में नहाने के दौरान दो लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं दिख रहे। खासकर युवा और बच्चे जान जोखिम में डालकर गहरे पानी तक पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने रविवार को यहां का निरीक्षण करने के दौरान पाया कि कई लोग एनीकट के बांध के उपर वाले गहरे पानी के क्षेत्र में भी नहा रहे हैं। जो कि खतरे से खाली नही है और यहीं पर पहले दो मौतें इसी साल हो चुकी है। विंडबना यह

है कि आसपास क्षेत्र में न तो प्रतिबंध से संबंधित कोई बोर्ड लगाया गया है और ना ही सुरक्षा की दृष्टि से गोताखोर या पुलिस की वहां व्यवस्था रखी गई है। जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन ने इस संवेदनशील मामले में केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शायद अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। उल्लेखनीय रहे कि जिला प्रशासन ने हादसों के बाद इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की थी और लोगों को नदी में उतरने से मना किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका अस्सर दिखाई नहीं दे रहा। न तो मौके पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर आ रहे हैं और न ही लोगों में डर दिखाई दे रहा है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिला चिकित्सालय बीजापुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने एक बार फिर जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर गंभीर अवस्था में भर्ती युवक को नया जीवन दिया है। विकासखंड उसूर निवासी 25 वर्षीय सुरेश काम्र को पेट दर्द, पेट फूलना, उल्टी तथा मल त्याग बंद होने की शिकायत के बाद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने मरीज की हालत को देखते हुए तत्काल सोनोग्राफी और आवश्यक लैब जांच कराई। जांच रिपोर्ट में मरीज को गैंग्रीनस सिम्माॅइड वॉल्वुलस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित पाया गया। यह बड़ी आंत के अंतिम हिस्से के मुड़ जाने की



खतरनाक स्थिति होती है, जिससे आंत में रुकावट पैदा हो जाती है और रक्त प्रवाह बाधित होने से आंत का हिस्सा सड़ने लगता है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर मरीज की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर के निर्देश पर तत्काल सर्जिकल टीम गठित की गई। टीम में सर्जन डॉ. रवि मढ़रिया, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. नरोत्तम सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहे। सभी जांच रिपोर्ट और मरीज की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद 23

मई को ऑपरेशन किया गया। सर्जन डॉ. रवि मढ़रिया ने एक्सप्लोरेटरी लैपरोटॉमी प्रक्रिया के माध्यम से सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान आंत के प्रभावित और सड़े हुए हिस्से को निकालकर पुनः जोड़ने की जटिल प्रक्रिया पूरी की गई। वर्तमान में मरीज की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय निगरानी में उसका उपचार जारी है। कलेक्टर विश्वदीप, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.



बी.आर. पुजारी के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय बीजापुर में लगातार गंभीर एवं जटिल बीमारियों का सफल उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों के कारण अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भी समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल रहा है। इस सफल सर्जरी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि अब ग्रामीण अंचलों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों पर

निर्भर रहने की आवश्यकता कम होती जा रही है और शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आमजन का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।

गैंग्रीनस सिम्माॅइड वॉल्वुलस क्या है?

गैंग्रीनस सिम्माॅइड वॉल्वुलस बड़ी आंत के अंतिम हिस्से के मुड़ जाने से होने वाली गंभीर स्थिति है। इससे आंत में रुकावट आ जाती है और रक्त प्रवाह बाधित होने लगता है। समय पर इलाज नहीं मिलने पर आंत सड़ने लगती है और मरीज की जान को खतरा हो सकता है। चिकित्सकों के अनुसार तेज पेट दर्द, पेट फूलना, उल्टी और मल त्याग बंद होना इसके प्रमुख लक्षण हैं।

15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित बैंक खातों के संबंध में जारी निर्देशों का पालन निरंतर जारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

पंचायत संचालनालय द्वारा 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के पृथक लेखांकन एवं पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में पंचायत संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/15वे वित्त/1123/2020-21/58 दिनांक 03 जुलाई 2020 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के पृथक लेखा संधारण के लिए जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार पृथक बैंक खाते खोले जाएं। साथ ही जिला स्तर पर यथासंभव एक ही बैंक में खाते संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके पश्चात पंचायत संचालनालय द्वारा संशोधित पत्र क्रमांक/15वे वित्त/1123/2020-21/60 दिनांक 04 जुलाई 2020 जारी कर जिलों को बैंक चयन के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान की गई। संशोधित निर्देशों में भी यह स्पष्ट किया गया कि 15वें वित्त

आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि के पृथक लेखांकन हेतु जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अलग-अलग बैंक खाते नियमानुसार खोले जाएं तथा संभव हो तो सभी खाते एक ही बैंक में संचालित किए जाएं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा पत्र क्रमांक/2886/जि.पंच./लेखा/15 वे वि.आ./2020 दिनांक 08 जुलाई 2020 के माध्यम से संबंधित बैंक में खाते खोले गए। इसके उपरांत आज दिनांक तक उक्त बैंक खातों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी संबंध में पंचायत संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र क्रमांक/15वे वित्त/1206/2021/395 दिनांक 20 दिसंबर 2021 के माध्यम से यह निर्देश भी जारी किया गया कि 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित बैंक खातों में किसी प्रकार का परिवर्तन आयुक्त, पंचायत संचालनालय की पूर्वं अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाएगा। जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा संचालनालय से प्राप्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्यासा चांपा: भीषण गर्मी में एक भी सार्वजनिक प्याऊ नहीं, सूचना देने के बाद भी नहीं जगे सीएमओ

■ 'वाटर एटीएम है'

कहकर पल्ला झाड़ रहे सीएमओ, हकीकत में वाटर एटीएम ही सूखे, जनता खरीदकर पीने को मजबूर, एसी दफ्तर में बैठा प्रशासन, सड़क पर झुलसती जनता

चांपा/मूक पत्रिका

नगर में भीषण गर्मी के बीच आम जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन नगर पालिका की उदासीनता और लापरवाही ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। हैरानी की बात यह है कि पूरे चांपा नगर में एक भी सार्वजनिक प्याऊ संचालित नहीं है, जबकि तापमान लगातार बढ़ रहा है और रोजाना कई लोग प्यास से जूझ रहे हैं। जब इस गंभीर समस्या की जानकारी चांपा नगर पालिका



के सीएमओ राम संजीवन सोनवानी को दी गई, तो उनका जवाब और भी चौंकाने वाला रहा। सीएमओ ने कहा कि बस स्टैंड और बीडीएम अस्पताल में वाटर एटीएम लगे हैं, लोग वहीं से पानी पी लें। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। स्थानीय लोगों के अनुसार, वाटर एटीएम लंबे समय से बंद पड़े हैं और उनमें पानी तक नहीं आ रहा। बीडीएम अस्पताल में लगे वाटर एटीएम से कभी पानी आता है और कभी नहीं आता। ऐसे स्थिति में लोगों को बाहर से पानी खरीदकर पीना पड़ता है। स्थिति यह है कि बस स्टैंड और बीडीएम अस्पताल जैसे प्रमुख स्थानों पर रोजाना सैकड़ों-

हजारों लोग आते हैं, जिनमें यात्री, मरीज और उनके परिजन शामिल हैं। इस भीषण गर्मी में जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब लोग मजबूरी में दुकानों से महंगे दामों पर ठंडा पानी खरीदने को विवश हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि चांपा नगर पालिका और विशेषकर सीएमओ को आम जनता की तकलीफें से कोई सरोकार नहीं है। सूचना देने के बावजूद न तो वाटर एटीएम की मरम्मत कराई गई और न ही अस्थायी प्याऊ की कोई व्यवस्था की गई। लोगों का कहना है कि सीएमओ अपने एसी दफ्तर और एसी कार से बाहर निकलकर कभी जमीनी हालात देखने की जरूरत ही नहीं

समझते। नगरवासियों ने यह भी बताया कि पूर्व में जो भी सीएमओ पदस्थ रहे, कम से कम नगर में दिखाई तो देते थे और सफाई व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं का जायजा लेते थे। लेकिन वर्तमान सीएमओ का नगर में दर्शन तक दुर्लभ है। सुबह-सुबह सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी लेना भी वे जरूरी नहीं समझते। केवल बड़े अधिकारियों के दौरे के समय ही वे सक्रिय नजर आते हैं, उसके बाद फिर वही उदासीन रवैया। कुछ जागरूक नागरिकों ने यह भी कहा कि वर्तमान सीएमओ युवा हैं, उनसे नगर के विकास को लेकर सक्रियता और नए प्रयोगों की उम्मीद थी। उन्हें चाहिए था कि वे अपने कार्यों में रुचि लेते, जनता की समस्याओं को समझते और चांपा नगर के लिए कुछ नया करने का प्रयास करीं। लेकिन उनके व्यवहार और कार्यशैली से ऐसा प्रतीत होता है कि वे केवल औपचारिक ड्यूटी निभाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं।

आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के लिए राज्य सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में शीघ्र शुरू होगी सीएम हेल्पलाइन 1076



जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों को दी गई तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप प्रदेश में सीएमओ को और अधिक प्रभावी एवं जनकेंद्रित बनाने की दिशा में राज्य

सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत संचालित यह प्रणाली नागरिकों को शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं तक सरल पहुंच उपलब्ध कराने तथा उनकी शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित की गई है।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ प्रशिक्षण

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के मार्गदर्शन में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सलाहकार अनुराग दीवान सहित जिला पंचायत सीईओ, डीएफओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखंड स्तर के अधिकारी एवं विभाग प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण से जुड़े।बैठक में अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन शिकायतें पंजीत, मॉनिटरिंग व्यवस्था एवं शिकायत निराकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पोर्टल एवं डैशबोर्ड संचालन, शिकायतों के वर्गीकरण, ट्रैकिंग एवं समयसीमा आधारित निराकरण की तकनीकी प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

टोल फ्री नंबर 1076 सहित कई माध्यमों से दर्ज होगी शिकायत

वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप से भी मिलेगी सुविधा-प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप अथवा लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायत 24x7 दर्ज करा सकेगा। शिकायत दर्ज होते ही शिकायतकर्ता को एक यूनिक शिकायत क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति, संबंधित विभाग एवं अधिकारी की जानकारी तथा समाधान की समयसीमा देख सकेगा। सीएम हेल्पलाइन सेंटर सप्ताह के सातों दिन एवं चौबीसों घंटे संचालित रहेगा, जिससे नागरिकों को किसी भी समय अपनी समस्या दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक भी इस सुविधा का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें 7

तकनीक आधारित मॉनिटरिंग से बढ़ेगी जवाबदेही-लंबित शिकायतों पर रहेगी मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी

शिकायत दर्ज होने के पश्चात संबंधित विभाग एवं अधिकारी तक प्रकरण तत्काल ऑनलाइन माध्यम से पहुंच जाएगा। पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ी होगी, जिससे प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी तथा शिकायतों के अनावश्यक लंबित रहने की संभावना कम होगी। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि शिकायतों के निराकरण के बाद संबंधित नागरिक से फीडबैक लिया जाएगा। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने पर ही शिकायत का अंतिम निराकरण माना जाएगा। यदि शिकायतकर्ता असंतोष व्यक्त करता है, तो शिकायत स्वतः पुनः सक्रिय होकर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित स्तर पर भेज दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

पारदर्शी एवं जनकेंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शासन और जनता के बीच मजबूत होगा संवाद एवं विश्वास

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को तकनीकी एवं प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बनाना, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा शासन और जनता के बीच पारदर्शिता एवं विश्वास को बढ़ावा देना है। इस पहल से आम नागरिकों की समस्याओं का घर बैठे एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। राज्य सरकार की यह नई व्यवस्था सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनसुविधा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे नागरिकों को शासन की सेवाओं का लाभ अधिक सरलता एवं प्रभावशीलता के साथ प्राप्त होगा।

संपादकीय

बद्रीनाथ से तीर्थ यात्रियों को लेकर लौट रहे एक हेलिकॉप्टर को तकनीकी कारणों से टिहरी के चंबा-आराकोट क्षेत्र में आपात स्थिति में उतरना पड़ा। इस दौरान बिजली की तारों के संपर्क में आने से हेलिकॉप्टर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा।उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंची-ऊंची चोटियों और धार्मिक स्थलों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पर्यटन का कारोबार राज्य की अर्थव्यवस्था

का मुख्य आधार है। खासकर चार धाम यात्रा के लिए यहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।

राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उस लिहाज से व्यवस्थागत ढांचे का विस्तार नहीं हो पाया है।पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से यहां के मौसम में अचानक बदलाव आने से भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं आम बात हैं। ऐसे में पर्यटकों को कई तरह की मुश्किलों

का सामना करना पड़ता है। यहीं नहीं, पर्यटकों को ले जाने और वापस लाने वाले हेलिकॉप्टर के हदसाग्रस्त हो जाने की घटनाएं भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं।ऐसी ही एक घटना बुधवार सुबह हुई, जब बद्रीनाथ से तीर्थ यात्रियों को लेकर लौट रहे एक हेलिकॉप्टर को तकनीकी कारणों से टिहरी के चंबा-आराकोट क्षेत्र में आपात स्थिति में उतरना पड़ा।

इस दौरान बिजली की तारों के संपर्क में आने

से हेलिकॉप्टर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा, हालांकि उसमें सवार यात्री सुरक्षित हैं।उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है।

मगर सवाल है कि सरकार के ये कदम क्या सिर्फ राजस्व अर्जित करने तक सीमित हैं,

या पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को भी केंद्र में रखा जाता है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहाड़ी प्रदेश होने के नाते क्षेत्रीय मौसम में बदलाव का सटीक पूर्वानुमान लगाने की व्यवस्था हो, ताकि पर्यटकों और परिवहन एजेंसियों को पहले ही संभावित खतरे से सतर्क किया जा सके।

इससे पहले भी चार धाम यात्रा मार्ग पर हेलिकॉप्टरों के हादसे का शिकार होने की

घटनाएं हो चुकी हैं। मगर ऐसा लगता है कि इन हादसों से शासन-प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। हालांकि, सरकार की ओर से धार्मिक यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है, लेकिन जब तक इसे कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार नहीं हो पाएगा।

हमारे देश का राजनीतिक तापमान तो वर्षपर्यंत उच्च रहता आया है और चुनावी इलाकों में इसके वैचारिक हीट स्ट्रोके से सिस्टम का झुलसना स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन जब मई-जून के महीने में मौसमी तापमान जानलेवा स्तर तक खतरनाक रूप से चढ़ता जाता है तो लोग बाग परेशान हो उठते हैं। फिर अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गलतियों पर पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि विकास के नाम पर आधुनिक भारतीय सभ्यता विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त हमारे हुक्मरान तमाशबीन बने बैठे हैं, क्योंकि हरेक आपदा को अवसरों में बदलकर अपनी कमाई बढ़ाने का धंधा उन्होंने सीख लिया है।

भारत में जानलेवा हुई गर्मी के साइड इफेक्ट्स समझिए, इसके कारण और बचाव के उपाय जानिए

शहरों में सभी भारत के थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट हमें चेतानी है कि देश के 50 प्रतिशत से ज्यादा शहरों में भीषण गर्मी का खतरा ‘अधिक’ से लेकर ‘बेहद अधिक’ के स्तर तक पहुंच चुका है। और तो और, साल 2015 से 2020 के दरम्यान लू वाले दिनों का औसत 7.4 दिन से बढ़कर 32.2 दिन हो गया है, और यह लगातार बढ़ रहा है। इसका गहरा दुष्प्रभाव हमारी सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ने के आसार प्रबल हैं।

हमारे शहरों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि वो अंधाधुंध विकास की होड़ में अपनी हरियाली उजाड़कर उन्हें कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करते जा रहे हैं। लिहाजा, भारत में गर्मी अब हर साल एक नया रेकॉर्ड बना रही है। चिंताजनक बात यह है कि दिन तो तपते ही हैं, अब रातों भी तपने लगी हैं और



राहत देने वाली नहीं रहें। इस 20 मई को दिल्ली ने मई महीने में 13 साल की सबसे गर्म रात देखी, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। 21 मई को स्थिति उससे भी ज्यादा बुरी हुई।इस प्रकार से हाल के बरसों में हीटवेव की तीव्रता, उसका समय और सीमा अभूतपूर्व रूप से बढ़े हैं। इससे शहरों पर संकट ज्यादा है, जो घंटती हरियाली, बढ़ते कंक्रीट स्ट्रक्चर और प्रदूषण की वजह से अबर्न हीट आइलैंड इफेक्ट झेल रहे हैं।

इससे हमारे कामकाज पर भी नकारात्मक असर पड़ चुका है, क्योंकि मौसम की यह मार दोतरफा है- सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ चुकी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक, 2025 में हीट स्ट्रोके के सात हजार से ज्यादा सस्पेक्टेड केस सामने आए थे। हालांकि माना जाता है कि भारत में

जाती है। लिहाजा यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। एक आकलन के मुताबिक, यदि यही हाल रहा तो 2030 तक गर्मी की वजह से भारत की जीडीपी का 4.5 प्रतिशत प्रभावित होगा। ये सारे आंकड़े एक गंभीर चेतावनी हैं। चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम के और बिगड़ने की आशंका है, इसलिए बेहतर रहेगा अगर हमलोग अपनी तैयारी पहले से कर लें।

भारत में खतरनाक गर्मी बढ़ने के प्रमुख कारण जानिए – भारत में खतरनाक गर्मी बढ़ने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं- पहला, जलवायु परिवर्तन- धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार मानव गतिविधियों से पैदा हुई ग्लोबल वार्मिंग ने भारत में हीटवेव को अधिक लंबा और तीव्र बना दिया है। दूसरा, जंगलों की कटाई- पेड़ प्राकृतिक कूलिंग

से होने वाले खतरे निम्नलिखित हैं- हीट स्ट्रोके, डिहाइड्रेशन, हार्ट और बीपी की समस्या, बच्चों और बुजुर्गों में मृत्यु जोखिम, फसल नुकसान, बिजली और पानी संकट श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी, भारत में हीटवेव से स्वास्थ्य संकट तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ये हैं व्यक्तिगत स्तर पर बचने के प्रमुख निदान – व्यक्तिगत स्तर पर बचने के प्रमुख निदान इस प्रकार हैं- पहला, दोपहर में बाहर निकलने से बचें, विशेषकर 12 बजे से 4 बजे तक। दूसरा, पर्याप्त पानी पिएं, ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी। तीसरा, हल्के सूती कपड़े पहनें, गहरे रंग और टाइट कपड़ों से बचें। चौथा, शरीर को ठंडा रखें, सिर ढके, छाता प्रयोग करें, गीला कपड़ा रखें। पांचवां, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान, उन्हें बंद गर्म कमरों में न रखें। हमें सामाजिक और सरकारी स्तर पर निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए

सामाजिक और सरकारी स्तर पर निम्नलिखित – कदम उठाने चाहिए-

पहला, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण- यह सबसे सस्ता और प्रभावी उपाय है। दूसरा, तालाब और जलस्रोत बचाना- स्थानीय तापमान कम करने में मदद मिलती है। तीसरा, कूल रूफ अभियान- सफेद या परावर्तक छतें घरों को ठंडा रखती हैं। चौथा, शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाना- पार्क ग्रीन कॉरिडोर, छायादार सड़कें। पांचवां, प्रदूषण नियंत्रण- स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देना।

क्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के पास राजनीतिक जमीन है?

(अवतेंश चित्राश) कॉकरोच पृथ्वी पर डायनासोर से भी पहले से मौजूद जीव माना जाता है। यह एक निशाचर कीड़ा है, जो अंधेरी, गर्म और नम जगहों में पनपता है।सोशलमीडिया हैंडल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के पास राजनीतिक जमीन नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जमीन तैयार करने के बाद अस्तित्व में आई थी। नेपाल में जेन-जी आंदोलन राजनीतिक रूप से खोखली हो चुकी व्यवस्था की पृष्ठभूमि में खड़ा हुआ था, जबकि बांग्लादेश में बदलाव की जमीन मुख्यतः मजहबी कट्टरता पर आधारित थी। ऐसे में सवाल यह है कि सोशलमीडिया पर बने हैंडल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के पास राजनीतिक आधार क्या है, सिवाय इसके कि वह केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है? वह पूरे राजनीतिक तंत्र का विरोध से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे।

एक कहावत है—भागते भूत की लंगोटी ही सही – दरअसल, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के कर्ताधर्ता अभिजीत दीपके ने कुछ ऐसा ही किया है। सोशल मीडिया के इस दौर में, जब भ्रम आग से भी तेज गति से फैलता है, तब भारत के चीफ जस्टिस का एक शब्द कॉकरोच का दीपके ने जिस तरह इस्तेमाल किया, उसने उसे अचानक चर्चा के केंद्र में ला दिया।

हालांकि, इस भ्रम के टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि केजरी के पास कोई ठोस नैतिक आधार नहीं है। और राजनीति में वैचारिक व नैतिक जमीन का होना पहली शर्त माना जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे समझने के लिए उस संदर्भ को समझना जरूरी है, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच शब्द को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। यह संदर्भ स्वयं युवाओं, विशेषकर जेन-जी, के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती को उजागर करता है। जेन-जी के भीतर विभाजन की शुरुआत ही आरक्षण व्यवस्था से हो जाती है, जो अवसर की समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आती है। सवाल यह है कि अभिजीत दीपके इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे?

कहां से शुरू हुआ यह मामला?– पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट के वकील संजय दुबे की एक याचिका से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अयोग्य वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने का विरोध किया था। इस याचिका की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस

जांयमल्य बागची की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने संजय दुबे से पूछा कि क्या उनके पास अपने सीनियर एडवोकेट के दर्जे के लिए मुकदमा लड़ने के अलावा कोई और मामला नहीं है? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, पूरी दुनिया शायद सीनियर दर्जे के लिए पात्र हो सकती है, लेकिन कम-से-कम आप नहीं हैं। यदि हाई कोर्ट आपको सीनियर घोषित भी कर देता है, तो हम आपके पेशेवर आचरण को देखते हुए उसे रह कर देंगे। सुनवाई के दौरान वकीलों की कानून की डिग्रियों की जांच प्रक्रिया का मुद्दा भी उठा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों द्वारा डाली जा रही सामग्री को देखकर उन्हें कई वकीलों की कानून की डिग्रियों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह होता है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे किसी उपयुक्त मामले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के कई वकीलों की डिग्रियों की सत्यता की जांच सीबीआई से कराई जा सके, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कई कारणों से इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।

इसी दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता संजय दुबे से कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं, जो व्यवस्था पर लगातार हमला करते रहते हैं। क्या आप भी उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि कुछ युवा रोजगार न मिलने और अपने पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें से कुछ मीडिया में पहुंच जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो कुछ अन्य प्रकार के एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस को इन गतिविधियों को पढ़ने के बाद सवाल उठता है कि क्या हमारे सिस्टम में योग्य युवाओं की तुलना में अयोग्य लोगों को अधिक अवसर और लाभ नहीं मिल रहा? और इसी संदर्भ में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभिजीत दीपके योग्य युवाओं के साथ खड़े हैं या उन अयोग्य कॉकरोचों के साथ, जिनकी ओर चीफ जस्टिस ने संकेत किया था?

अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक उल्लेखनीय प्रसंग – योग्यता और अयोग्य कॉकरोचों की इस चर्चा के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक प्रसंग भी उल्लेखनीय है। अभिजीत दीपके, केजरीवाल के आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उनकी तुलना महात्मा गांधी से करते हैं।

तकनीक और आराम की बढ़ती चाह के बीच खामोश होते रिश्ते और बदलता इंसान का चेहरा

सुविधाओं की अंधी दौड़ में हम जरूरत और लालच के बीच की रेखा को मिटा रहे हैं। नदियों के सूखते किनारे, उजाड़ होते पहाड़ और निर्दोदिन जहरीली होती फिजा इंसानी लालच की कहानी चीख-चीख कर सुना रही हैं। आज आधी दुनिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध की आग में झुलस रही है, जिसका कुप्रभाव मनुष्यों के साथ ही प्रकृति पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन राख के ढेर में बदलते जा रहे हैं। तकनीक और नैतिकता के संबंध को समझाने के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध कथन है- ‘हमारी तकनीकी प्रगति इतनी तेज हो चुकी है कि वह मानवता, संवेदनशीलता, नैतिकता और आपसी समझ से भी आगे निकल गई है।’

(अलका ‘सोनी’)

आज सुविधाओं का युग है, जहां हर इंसानी जरूरत के लिए अभूतपूर्व सुविधाएं, तकनीक और विकल्प मौजूद हैं। जिनकी वजह से हमारा जीवन तेज, सरल और आरामदायक हो गया है। मगर हर सुविधा अपने साथ एक नैतिक प्रश्न भी लेकर आती है कि क्या हम इन सुविधाओं के उपयोग के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, जितना कि इन्हें पाने के लिए उत्साहित होते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यही द्रढ़ सुविधाओं के बक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने लिए धरती से कितना ले रहे हैं! महात्मा गांधी ने कहा था, ‘पृथ्वी हर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर मनुष्य के लालच के लिए नहीं।’

सुविधाओं की अंधी दौड़ में हम जरूरत और लालच के बीच की रेखा को मिटा रहे हैं। नदियों के सूखते किनारे, उजाड़ होते पहाड़ और निर्दोदिन जहरीली होती फिजा इंसानी लालच की कहानी चीख-चीख कर सुना रही है। आज आधी दुनिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध की आग में झुलस रही है, जिसका

कुप्रभाव मनुष्यों के साथ ही प्रकृति पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन राख के ढेर में बदलते जा रहे हैं। तकनीक और नैतिकता के संबंध को समझाने के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध कथन है- ‘हमारी तकनीकी प्रगति इतनी तेज हो चुकी है कि वह मानवता, संवेदनशीलता, नैतिकता और आपसी समझ से भी आगे निकल गई है।’

आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत संवाद कर सकते हैं, लेकिन यही सुविधा फर्जी खबरों, नाहक परेशान करने और ‘साइबर बुलिंग’ यानी इंटरनेट पर डराने-धमकाने या प्रताड़ित करने की घटनाओं को भी जन्म दे रही है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां झूठी खबरों के कारण समाज में तनाव और हिंसा तक फैल जाती है। इन सारी घटनाओं से यही पता चलता है कि सुविधा के साथ विवेक और नैतिकता का होना कितना आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में भी सुविधाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के लिए ई-वाणिज्य की सुविधा ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन अनावश्यक खरीदारी और पैकेटों के कचरे ने पर्यावरण पर भारी दबाव भी डाला है। यहां सवाल उठता है कि क्या

हम महज अपनी सुविधा के लिए प्रकृति का दोहन कर सही कर रहे हैं? आज इन सुविधाओं के आदि हो चुके लोग, अपने से कम संपन्न रिश्तेदारों के घर जाने से भी कतराते हैं। कारण वहां उन सुविधाओं का अभाव होना है, जिनकी उन्हें आदत पड़ चुकी होती है। पहले जहां परिवार के साथ बैठकर बातचीत होती थी, अब वही समय मोबाइल स्क्रीन के सामने बीतता है। इसकी वजह से पारिवारिक मूल्य भी बिखर रहे हैं। अगर हम इसी तरह सुविधाओं में डूबे रहेंगे और अपने संबंधों और जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे, तो यह हमारे लक्ष्य से भटकने का ही संकेत है। पर्यावरण के संदर्भ में सुविधाओं की कीमत तो और भी गंभीर है। वातानुकूलन यंत्र, कार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने जीवन को आरामदायक बनाया है, लेकिन इनके कारण होने वाले प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे हाथों अब कुछ नहीं बचा। हर व्यक्ति अपनी छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सकता है। जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा की बचत और जिम्मेदार तरीके से उसका उपभोग

कर बड़े परिवर्तन की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। सुविधाओं की असमानता भी एक बड़ा नैतिक मुद्दा है। एक ओर कुछ लोग अत्याधुनिक तकनीकों का आनंद ले रहे हैं, दूसरी ओर बहुत से लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। भीमराव आंबेडकर ने कहा था, ‘मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि वह कितना धन अर्जित करता है, बल्कि इस बात में है कि वह समाज के लिए कितना योगदान देता है।’ यह कथन हमें याद दिलाता है कि सुविधाओं का सही उपयोग तभी है, जब वह समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो, क्योंकि यह समाज में अस्तोष को बढ़ावा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं ने नई संभावनाएं खोली हैं, लेकिन डिजिटल विभाजन ने एक नई असमानता को जन्म भी दिया है। जैसा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन विद्यार्थियों के पास इंटरनेट और उपकरण नहीं थे, वे पीछे छूट गए। यहां नैतिक जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ हर जागरूक नागरिक की है कि वह इस अंतर को कम करने में योगदान दे।

सुविधाओं के प्रति अत्यधिक निर्भरता भी चिंता का विषय है। जब हम हर छोटे काम के लिए तकनीक पर निर्भर हो जाते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता कमजोर हो जाती है। हमें अपनी क्षमताओं को जरूर विकसित करना चाहिए, लेकिन उन पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए। बल्कि समाधान यह है कि हम सुविधाओं का उपयोग विवेक, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ करें। हमें यह समझना होगा कि हर सुविधा के साथ एक नैतिक दायित्व भी जुड़ा होता है। अगर हम तकनीक का उपयोग समाज के हित में करें, पर्यावरण का ध्यान रखें और अपने संबंधों को प्राथमिकता दें, तो सुविधाएं हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। सुविधाओं के बरक्स हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रगति केवल भौतिक उन्नति को पाने की अंधी दौड़ में नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के संरक्षण में है। जब सुविधा और नैतिकता साथ-साथ चलें, तभी एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है।

धीषण गर्मी में पानी जैसी मूलभूत सुविधा को नजरअंदाज करना नगर पालिका की संवेदनहीनता को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि खबरों और जनआक्रोश के बाद नगर पालिका और सीएमओ इस गंभीर समस्या पर कौं ठोस कदम उठाते हैं या चांपा की जनता यही प्यास से जूझने को मजबूर रहेगी।

सांक्षिप्त समाचार

चूना पत्थर के अवैध परिवहन पर हाईवा जप्त



सारंगढ़ बिलाईगढ़, 25 मई 2026/ खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु खनिज टीम द्वारा सोमवार को तहसील बरमकेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौण खनिज चूनापत्थर के अवैध परिवहन करते हुए हाईवा क्रमांक छत्त-13२-क- 6626 पर कार्यवाही करते हुए थाना बरमकेला के सुरक्षार्थ में दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर खनि अधिनियम के तहत यह कार्यवाही की गई।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन पर सारंगढ़ बस स्टैंड में यात्री सुविधा विस्तार के लिए 50 लाख स्वीकृत

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 25 मई 2026/उप मुख्यमंत्री सह नगरीय प्रशासन विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सारंगढ़ नगरपालिका परिषद के बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किया है। विभाग ने इसकी मंजूरी का आदेश जारी कर चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट प्रावधानों के अनुरूप अधोसंरचना मद से यह राशि मंजूर की है।

घरघोड़ा तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता के 10 दिनों मे पिता और माता का निधन, परिवार में शोक की लहर



घरघोड़ा। घरघोड़ा तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता की माता सावित्री गुप्ता का सोमवार को आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज कुमार गुप्ता के पिता कृष्ण गोपाल का निधन 16 मई 2026 को हुआ था। परिवार

अभी इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि 25 मई 2026 को उनकी माता ने भी अंतिम सांस ले ली। महज 10 दिनों के भीतर माता-पिता दोनों का साया उठ जाने से परिवार गहरे सदमे में है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले करीब दो महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। परिवार द्वारा लगातार उनका उपचार कराया जा रहा था, लेकिन नियति के आगे सभी प्रयास असफल रहे। माता पिता दोनों नाती पोतो से खेलता भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए। माता-पिता दोनों के निधन से तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता और उनका पूरा परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ है। इस दुखद समाचार के बाद प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

लॉगबुक से लेकर AI-पावर्ड केयर तक सैमसंग ने भारत में कस्टमर सर्विस के 30 साल पूरे किए

भारत के सबसे बड़े कंप्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, सैमसंग ने भारत में अपनी कस्टमर सर्विस के 30 साल पूरे किए हैं। यह 1990 के दशक के बीच में दिल्ली में एक छोटे से सर्विस ऑपरेशन से देश के सबसे बड़े और सबसे डिजिटली-कनेक्टेड कस्टमर केयर इकोसिस्टम में से एक बनने तक का सफ़र तय करता है। जब सर्विस अभी भी एनालॉग थी सैमसंग की कस्टमर सर्विस में बदलाव की कहानी भारत के अपने टेक्नोलॉजिकल बदलाव को काफ़ी हद तक दिखाती है — हाथ से लिखे शिकायत रजिस्टर, पेजर और फ़िज़िकल सर्विस विज़िट के ज़माने से लेकर AI-पावर्ड डायग्नोस्टिक्स, कनेक्टेड अप्लायंसेज और प्रेडिक्टिव केयर इकोसिस्टम तक। जब सैमसंग ने मार्च 1996 में भारत में अपना पहला सर्विस सेंटर खोला, तो देश बहुत अलग दिखता था। फ़ोन और इंटरनेट बहुत कम थे और कस्टमर रिक्रेस्ट भीड़-भाड़ वाले ऑफ़िस डेस्क पर रखे रजिस्टर में मैन्युअली रिकॉर्ड की जाती थीं। सैमसंग इंडिया के सर्विस ऑपरेशंस के डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने कहा, उस समय, कस्टमर केयर असल में बहुत पर्सनल होता था। कस्टमर अक्सर सीधे सर्विस सेंटर जाते थे क्योंकि घरों में टेलीफोन आम नहीं थे। सर्विस रिक्रेस्ट को रजिस्टर में हाथ से डाला जाता था, और इंजीनियर लॉगबुक, पेपर स्लिप और टूलकिट लेकर शहरों में घूमते थे। दिसंबर 1996 तक, सैमसंग पूरे भारत में 21 सर्विस सेंटर तक फैल चुका था। 1997 में, इंजीनियरों ने कस्टमर अलर्ट पाने के लिए पेजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया — यह उस समय एक छोटी लेकिन ज़रूरी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी।

कलेक्टर की अध्यक्षता में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

कलेक्टर द्वारा एग्रीस्टेक में शेष कृषकों का शीघ्र पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश

समस्त किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश

रासायनिक खाद का अधिक दर पर विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश

मूक पत्रिका/सारंगढ़-बिलाईगढ़, 25 मई 2026/कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में सोमवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उमेश साहू, डिप्टी कलेक्टर, वर्षा बंसल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आशुतोष श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि, शीतल भोई, डीएमओ सारंगढ़, अपेक्स बैंक नोडल, सहकारिता विभाग के अधिकारी, जिले के समस्त तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सारंगढ़, बरमकेला एवं



बिलाईगढ़, कृषि विभाग के मैदानी स्तर के समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर द्वारा जिले के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनागत एग्रीस्टेक में पंजीयन हेतु शेष बचे कृषकों का एक सप्ताह के अंदर शतप्रतिशत पंजीयन पूर्ण

करने के लिए निर्देशित किया गया। खरीफ 2025 में धान बेचने वाले ऐसे कृषक जिनका एग्रीस्टेक में पंजीयन नहीं हुआ था

उन कृषकों का 15 जून तक फ़र्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। कृषक 15 जून तक फ़र्मर रजिस्ट्री नहीं कराते है तो खरीफ 2026 में सहकारी

समिति में धान विक्रय से वंचित हो जायेंगे। साथ ही शासन की विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं से लाभ मिलना बंद हो जायेगा।

बैठक में कलेक्टर ने रासायनिक खाद विक्रय पर किसी भी प्रकार के अनियमितता या अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

8 करोड़ से अधिक नुकसान की आशंका, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना; जांच शुरू

ईटपाल के तेंदूपत्ता गोदाम में भीषण आग, 25 हजार बोरी जलकर खाक

मूक पत्रिका/ बीजापुर/आशीष पदमवार। जिले के ईटपाल स्थित तेंदूपत्ता गोदाम में सोमवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखी हजारों बोरी तेंदूपत्ता उसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक घटना में 8 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार आग दोपहर करीब 3 बजे लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में पूरा गोदाम धुएं और आग की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। हालांकि तेज लपटों और गोदाम में बड़ी मात्रा में संग्रहित तेंदूपत्ता होने के कारण आग पर काबू पाने में भारी मशक़त करनी पड़ी।



घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। प्रशासनिक अधिकारी और वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने में जुटी रही। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफ़रा-तफ़री का माहौल बन गया।

सीसीएफ़ बस्तर आलोक तिवारी ने बताया कि गोदाम की कुल क्षमता

लगभग 50 हजार बोरों की है। अब तक आठ समितियों के माध्यम से करीब 25 हजार वास्तविक बोरे गोदाम में पहुंच चुके थे। इनमें लगभग 12 से 13 हजार मानक बोरे शामिल थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

उन्होंने बताया कि घटना के समय आसपास की वनोपज समितियों के



प्रबंधक और श्रमिक लंच ब्रेक पर थे। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की एक संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि गोदाम परिसर में भोजन पकाना और ज्वलनशील वस्तुएं रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जब गोदाम में तेंदूपत्ता ढुलाई का

कार्य चल रहा था, तब गोदाम प्रभारी और जिम्मेदार कर्मचारी मौके पर मौजूद थे क्या? यदि शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उसकी जानकारी समय रहते कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल सकी? इन सवालों को लेकर स्थानीय लोगों में भी चर्चा बनी हुई है। प्रशासन ने आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

रायगढ़ की बेटी काव्या पटेल ने महाराष्ट्र

की धरती पर रचा इतिहास



और बाल्यकाल से ही कला साधना में निरंतर सक्रिय रही हैं।

बेटी की इस सफलता पर उनकी माता श्रीमती कामिनी पटेल ने काव्या की मेहनत, लगन एवं प्रशिक्षकों के कुशल निर्देशन की सराहना करते हुए हर्ष व्यक्त किया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए काव्या की इस उपलब्धि वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज कराया।

विदित हो कि काव्या पटेल सेंट टेरेसा स्कूल में कक्षा छठवीं की छात्रा हैं। शिक्षा के साथ-साथ उन्हें नृत्य एवं संगीत में विशेष रुचि है

काव्या की इस उपलब्धि से परिजनों, विद्यालय परिवार एवं नाते-रिश्तेदारों में खुशी और उत्साह का माहौल है। रायगढ़वासियों ने भी इस होनहार बेटी को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी हैं।

कोटवारी भूमि पर कैसे बने आलीशान मकान-बाड़ी ? सरिया तहसील में अवैध खरीद-फ़रोख़्त और कब्ज़े की चर्चाएं तेज... (पार्ट-01)

मूक पत्रिका/सारंगढ़-बिलाईगढ़// सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का सरिया तहसील क्षेत्र इन दिनों कई कारणों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्षेत्र में अवैध डोलोमाइट खनन, शासकीय भूमि पर कब्जे और कोटवारी भूमि के उपयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब कोटवारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा, खरीद-फ़रोख़ा और मकान-बाड़ी निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिससे राजस्व व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार सरिया तहसील क्षेत्र में डोलोमाइट पत्थर के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। क्षेत्र के कई गांवों में खदान संचालन और पत्थर केशरों में बड़े पैमाने पर पत्थर खपाए जाने की बातें स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सबसे गंभीर सवाल उन कोटवारी जमीनों को लेकर उठ रहे हैं, जिन्हें मूल रूप से ग्राम



कोटवारों के दायित्व निर्वहन और शासकीय व्यवस्था से जुड़े उपयोग के लिए चिन्हित किया गया था। अब इन्हीं जमीनों पर कथित रूप से निजी उपयोग, निर्माण कार्य और कब्जे की चर्चां ने नया विवाद खड़ा कर दिया

है।

स्थानीय लोगों के बीच यह सवाल प्रमुखता से उठ रहा है कि आखिर कोटवारी भूमि, जिसकी प्रकृति शासकीय और सीमित उपयोग वाली मानी जाती है, वहां किस

आधार पर मकान-बाड़ी और अन्य निर्माण खड़े हो रहे हैं। यदि किसी भूमि की खरीदी-बिक्री या निजी उपयोग की अनुमति नहीं है, तो फिर इस तरह के निर्माण और कथित लेन-देन कैसे संभव हो रहे हैं? क्षेत्र में यह

भी चर्चा है कि कुछ स्थानों पर कोटवारी भूमि की अवैध खरीद-फ़रोख़्त का खेल लंबे समय से चल रहा है और इस पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से मामला और गंभीर होता जा रहा है।

इन मामलों के सामने आने के बाद राजस्व विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। लोगों के बीच चर्चा है कि जिन जमीनों की निगरानी और अभिलेखीय सुरक्षा की जिम्मेदारी व्यवस्था पर है, वहां लगातार विवाद और कब्जे की स्थिति आखिर कैसे बन रही है। इसी बीच संबंधित ग्राम कोटवार की जीवनशैली और कोटवारी भूमि पर निर्माण को लेकर भी क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इन दावों और चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस पूरे मामले में जुड़े तथ्यों, संबंधित भूमियों और जिम्मेदार पक्षों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिन पर अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

मृतक का बेटा बनकर हड़पी 3.25 हेक्टेयर जमीन,फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

सुरजपुर। जमीन हड़पने के लिए ऐसा फर्जी खेल खेला गया जिसने राजस्व रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। मृत व्यक्ति का फर्जी वारिस बनाकर करोड़ों की जमीन अपने नाम कराने वाले आरोपी को आखिरकार चंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला ग्राम वंशीपुर की 3.25 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है, जहां 75 वर्षीय शिवचरण निवासी ग्राम परमेश्वरपुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि अशोक सिंह और उसके पिता लक्ष्मण सिंह ने धोखाधड़ी, छल और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन पर कब्जा कर लिया है। जांच एसडीओपी प्रतापपुर को सौंपी गई। दस्तावेजों और कथनों की पड़ताल में खुलासा हुआ कि शिवभजन की मौत 20 सितंबर 2014 को हो चुकी थी, लेकिन मौत के दो साल बाद 20 मई 2016 को फर्जी नामांतरण आदेश जारी कराया गया और 27 जून 2016 को फौती नामांतरण में लक्ष्मण सिंह पिता जोखन सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी मुआवजा और नौकरी हासिल करने की नीयत से खुद को मृतक का वैध उत्तराधिकारी साबित कर रहे थे। मामले में थाना चंदौरा में अपराध क्रमांक 56/26 के तहत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120(बी), 34 भादसं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया।

